12.21 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

CYCLONE IN COASTAL PARTS OF ORISSA, ANDHRA PRADESH AND TAMIL NADU STATES.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के तटवर्ती भागों में आये हाल के समुद्री तूफान के कारण जनजीवन, सम्पत्ति और फसलों को भारी हानि होने के समाचार तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

12.22 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): According to the information furnished by the I.M.D. a depression had formed over Bay of Bengal centred at 8.30 A.M. on the 15th October, 1982 about 550 kms. south-east of Kalingapatnam. It intensified into a deep depression by the same evening. The system rapidly intensified into a severe cyclonic storm on the morning of October 16, 1982 and lay centred about 120 kms. south east of Kakinada. It moved in a north westerly direction and crossed Andhra Coast near Kakinada after midnight of October 16/17, 1982. It, however, weakened rapidly and became unimportant after crossing the coast.

2. The initial information regarding formation of a deep depression and associated adverse weather over the areas of Coastal Andhra Pradesh was issued to All India Radio on the evening of 15th October 1982 which was duly broadcast. IMD also issued warnings to the Chief Secretary and other Government Officials of Andhra Pradesh, Port Authorities and fishery officials. Subsequently, cyclonic warning bulletins were regularly issued to All India Radio from the 16th morning onwards ending with dewarning bulletin issued on the morning of 17th October 1982. Advance intimation about the occurrence of severe weather in specified areas of Coastal Andhra Pradesh was given through regular special cycline warnings over the All India Radio.

3. According to the State Government of Andhra Pradesh the cyclone caused heavy rains in Visakhapatnam district on 17th October inundating areas and damaging roads etc. Five deaths have been reported so far in Visakhapatnam due to collapse of houses. Assessment of damage to public and private properties and crops is being done.

4. Relief operations were pressed into service at once and immediate gratuitous relief and feeding of people was arranged by the State Government.

5. Again on 18th October, a message was received by the Andhra Pradesh Government from the Meteorological Department that a severe cyclonic storm is centred 125 kms south east of Madras which is likely to cross between Madras and Nellore by late evening or night same day and with storm surge and gale speed of 110 to 120 kilometres per hour. Necessary warnings were issued again to the Chief Secretaries and officials of Government of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Port Authorities, fisheries officials etc. The cyclone hit Andhra

coast near Sriharikota on the midnight of the 18th October affecting coastal taluks of Gudur, Naidupet, Sullurpet, Nellore, Kovur, Indukurpet in Nellore and Prakasam districts and heavy to very heavy rains in Guntur, Krishna Cuddapah and Chittoor districts. There was rainfall in some other districts as well. Ten deaths in Nellore Distt. have been reported. Exgratia payment of Rs. 250 is being paid for houses damaged and 20 kgs. of rice is being supplied to those whose houses have been damaged. Estimate of damage is being carried out.

6. While the second cyclone crossed Andhra coastal area at Sriharikota, Madras city and Chingleput district of Tamil Nadu received stormy winds accompanied by rains under its influence. 400 people had to be evacuated from low lying areas in Madras city where some huts are reported to have been damaged. No report of loss of life has been received by the State Government. There was, however some los to cattle life and a number of boats and catamarans are also reported missing in Chingleput district. Some trees got up-rooted on Madras-Vijayawada highway and traffic was held up for about 6 hours which has now been cleared. Assessment of damage is being made by the Collector of Chingleput district.

7. According to India Meteorological Department, there is no report of cyclone having affected any part of Orrisa.

8. The State Governments of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have got a margin money of Rs. 8.58 crores and Rs. 8.59 crores respectively to meet the emergent expenditure on providing relief to the affected people.

9. I want to assure the Hon'ble Members that the Government of India will extend all possible assistance to the State Governments if they are unable to meet the situation within the margin money at their disposal.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उड़ीसा और आन्ध्र-प्रदेश आदि राज्यों में प्राय: तूफान की स्थिति पैदा होती रहती है। वैसे तो पूरे देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अकाल और कहीं तूफान की स्थिति बनती रहती है, लेकिन खासतौर से आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में तूफान प्राय: आता रहता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो निरन्तर चलती रहती है। वास्तव में यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें हमारा नियंत्रण भी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पर हम लोगों को बचाने के लिये काफी कुछ काम कर सकते हैं।

इन्सैट-1 जब आकाश में फेंका गया था, उस समय उससे यह उम्मीद थी कि उसके जरिये तूफान के बारे में और मौसम की अन्य तमाम जानकारियां हमें मिलेंगी, लेकिन यह अपने आपमें एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इन्सैट–1 असफल हो गया और सूचनाएं उससे हमें मिल सकती थीं, वह नहीं मिल पा रही हैं। इसलिये इस आपदा को नियंत्रित करने के लिये हमें जितनी पूर्व-सूचना मिल सकती थी, वह मिलने में कठिनाई हो रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विदेशी सरकारों ने जो तमाम इस प्रकार के सैटलाइट आकाश में छोड़े हुए हैं, क्या उनके जरिये वह ऐसी सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करते हैं जिससे मालूम हो सके कि इस प्रकार की आपदा आने वाली है और उसके आधार पर पहले से व्यापक तैयारी की जा सके ?

क्या मंत्री महोदय यह जवाब देने की कृपा करेंगे कि विदेशी उपग्रहों से यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह

[श्री हरिकेश बहादुर]

कितने दिन पहले हो जाती है ? क्या सरकार उससे कोई जानकारी लेने की कोशिश करती है या नहीं ?

जहां तक इस तूफान की तीव्रता का सवाल है, इसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाती कि यह कितनी तीव्र गति से आएगा और वायु की गति कितनी तेज रहेगी ? मैं जानना चाहूंगा कि तीव्रता की जानकारी करने के लिये क्या कोई अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है ? हमारा जो सिस्टम है, जिसके जरिये हम जानकारी करते हैं, उसको और भी अधिक समुन्नत बनाया जा सके और अधिक जानकारी उससे ली जा सके, इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

हमारे जो साइक्लोन वार्निंग राडार लगाये गये हैं, वह किस हद तक जानकारी देते हैं ? आज यह कहा जाता है कि राडार 400 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले तूफान की जानकारी दे सकता है । इससे हमें 24 घंटे पूर्व सूचना मिल सकती है । जो भी हमारे वार्निंग राडार हैं, उनकी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिये क्या कोई अनुसंधान कार्य हो रहा है । क्या इससे भी बेहतर किस्म के राडार लगाने की कोई योजना है और उसे आप क्रियान्वित करना चाहते हैं ? क्या आपने विदेशी सरकार से कोई वार्ता इस सम्बन्ध में की है, जिससे वैज्ञानिक सहायता मिल सके ?

अभी जो तूफान आया है इससे जन-धन की भारी क्षति हुई है । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 5 व्यक्ति मरे हैं ।

श्री बालेश्वर राम : 5 और 10 कहा है ।

श्री हरिकेश बहादुर : अखबारों में जो सूचनाएं हैं, उसमें इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है । आपने कहा है कि इसका और एसेसमैंट करने वाले हैं, तब आपको इसकी सूचना मिलेगी ।

हजारों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जन-धन की भारी क्षति हुई है और जब भी तूफान आता है तो इस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य-पूर्ण है, लेकिन जो राहत कार्य किया जाता है, उसमें माननीय मंत्री महोदय को विशेष रूप से यह देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार न हो । राहत कार्य के बीच में भ्रष्टाचार होता है, यह हमेशा की प्रक्रिया बनी हुई है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि 19 नवम्बर, 1977 को जो आंध्र प्रदेश में तूफान आया था वह बहुत भीषण था, उसमें हजारों की संख्या में लोग मरे और उस समय भी राहत कार्य के लिए जो सामग्री दी गई थी, उसको बहुत से लोगों ने, जिन के हाथ में यह राहत देने का कार्य था, उन्होंने उससे अपनी राहत का कार्य ज्यादा किया । यह बहुत ही दुखद स्थिति है, कि जब इतने भयंकर तूफान से लोग कष्ट में पड़े हों, उनके मकान गिरे हों, लोग बेघरबार हों तो ऐसी हालत में भी जो राहत के लिए सामग्री दी जाती है, उसमें भी लूट-खसोट होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि आप राहत के तौर पर कितना अनाज, कितना पैसा और कितनी दूसरी वस्तुएं जैसे कपड़ा वगैरह है, वहां पर भेज रहे हैं । साथ ही, वह सारी वस्तुएं वहां पर सही ढंग से वितरित हो सकें, इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? राज्य सरकार को किस प्रकार के निदेश इस संबंध में दिए जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय एक बहुत बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है । क्योंकि

जब मकान गिर जाते हैं, तो जिन लोगों के मकान गिरते हैं उनको मकान बनाने में सहायता देना आवश्यक हो जाता है। यहां पर मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रति व्यक्ति 250 रुपए मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में दिए जायेंगे। आप बताईए जिसका मकान गिरा है, वह 250 रुपए से क्या कर लेगा ? क्या वह 250 रुपए से अपना मकान बना पाएगा ? सभी लोग जानते हैं कि इतने पैसे से कुछ ही नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जैसे आप एक तरफ भारत में फाइवस्टार होटल्स बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको गरीब लोगों को सुविधा पहुंचाने के बारे में भी देखना होगा। मृतकों के परिवारों को जो सहायता राशि दी गई है, वह भी बहुत कम है, नाकाफी है। मेरी सरकार से मांग है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 10 हजार रुपए तथा जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, उनको कम से कम एक हजार रुपए दिए जायें। क्योंकि 250 रुपए में कुछ नहीं होगा, वह नाकाफी हैं। वैसे तो एक हजार रु० भी बहुत कम है, फिर भी वह 250 का तो चार गुना राशि है। इसीलिए म चाहता हूं कि इतनी सहायता आप तत्काल वहां पर दें। इसके अतिरिक्त घर बनाने के लिए बगैर व्याज के ऋण लोगों को दिए जायें, जिन पर किसी तरह का ब्याज न लिया जाए आप ऐसा नियम बना सकते हैं, तरीका सोच सकते हैं कि बिना सूद के लोगों को ऋण दिए जायें, जिसको वे कालांतर में वापस कर देंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें। सहायता देने के तरीके को आसान करने के संबंध में केन्द्रीय मंत्री मंडल की एक समिति बनने वाली थी, जब भी कभी देश में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदायें आयें, जैसे बाढ़, सूखा या तूफान आ जाता है। हो सकता है कि तूफान के समय ऐसी समिति बनाई गई हो, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें कि मंत्री मण्डलीय स्तर पर जो समिति बनाने की चर्चा हुई थी, जिसमें माननीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और योजना मंत्री उस के सदस्य थे ताकि प्रभावित राज्यों को समय पर आसानी से सहायता दी जा सके, अनुदान की राशि दी ज ए, उसको जल्दी निश्चित किया जाए, उस समिति के बारे में क्या हुआ ? यदि वे उस समिति के बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकें तो अच्छा होगा। वह समिति अब तक बनी या नहीं ? यदि कोई समिति बनी है तो वह इस दिशा में क्या कर रही है। इस मामले में वह क्या कर रही है ?

मेरा एक प्रश्न यह भी है कि जितनी जन धन की हानि हुई है, क्या उसकी जांच के लिए भारत सरकार कोई सेंट्रल टीम वहां भेजने वाली है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्वाइंट को नोट कर लें और स्पष्ट करें कि क्या उनका विचार कोई सेंट्रल टीम भेजने का है ?

एक माननीय सदस्य : उस टीम में कौन कौन से माननीय सदस्य होंगे, इस को भी स्पष्ट करें।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : हम लोग चार कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आप कहिए.....

श्री हरिकेश बहादुर : तामिलनाडु में पिछले 80 वर्षों में 34 बार तूफान आए हैं। तामिलनाडु में यह काम बहुत अच्छा हुआ है कि वहां कुछ सुरक्षा गृहों का निर्माण कर लिया गया है, कुछ प्रोटैक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह के सुरक्षा गृह तामिलनाडु में बनाए गए हैं, क्या सरकार दूसरे राज्यों को भी वैसे ही सुरक्षा गृह बनाने के लिए पैसा देगी ताकि समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वे तूफान की विभीषिका से बच सकें। उन लोगों को जब भी तूफान की आशंका हो, वे अपने

[श्री हरिकेश बहादुर]

परिवार को उन सुरक्षा गृहों में स्थानांतरित कर लें। अन्य राज्यों में सुरक्षा गृह बनाने की दिशा में सरकार का क्या विचार है, क्या उसके लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाएगा ताकि लोगों को समय पर सहायता देकर बचाया जा सके। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर भी प्रकाश डालने का कष्ट करें।

मान्यवर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एमर्जेंसी रिलीफ आर्गेनाईजेशन स्कीम बना रखी है। सन् 1963 के साइक्लोन के बाद यह बनी है। पब्लिकेशन डिवीजन की ओर से एक पुस्तिका गवर्नमेंट ने निकाली है--"हाऊ टू गार्ड अगेन्स्ट दैम"।

यह पब्लिकेशन्ज़ डिविज़न, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है। इसमें पेज 32 पर कहा गया है :--

"For emergencies resulting from natural calamities, the Ministry of Home Affairs, Government of India have drawn up an emergency relief organisation scheme."

यह जो इमर्जेन्सी रिलीफ आर्गनाइज़ेशन स्कीम है, क्या वह अब भी चलती है; अगर हां, तो इसके तहत क्या कार्यवाही हो रही है? जब कभी तूफान या किसी अन्य दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो इस स्कीम के तहत सरकारी मशीनरी तुरन्त काम में लगाई जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह सूचना मिली कि तूफान आने वाला है, तो इस योजना के अन्तर्गत जो संगठन बना हुआ है, क्या उसने कोई काम शुरू किया?

जब साइक्लोन या तूफ़ान खत्म हो जाते हैं, तो महामारियों का भीषण प्रकोप होता है।

Sir, the Ministry of State for Agriculture from Tamil Nadu is not looking to these problems properly. He is just talking.

RAO BIRENDRA SINGH: He knows the problem very well. He knows that what you are saying is not correct.

श्री हरिकेश बहादुर: तूफ़ान के समाप्त होने के बाद जो महामारी आती है, क्या उसके बारे में सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है, ताकि लोगों को महामारी तथा इस प्रकार की अन्य विपत्ति से बचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित बातों के बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इन विपदाओं को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए कारगर कदम उठाएं जाएं। साथ ही सुरक्षा-गृह बनाने के बारे में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि जब कभी तूफ़ान आने की आशंका हो, तो लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षा-गृहों में रखा जाए। यह मेरी मांग भी है और मैं इस बारे में जानकारी भी चाहता हूं।

श्री बालेश्वर राम: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफ़ी व्यापक प्रश्न पूछा है। हम सब इससे सहमत हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और एक राष्ट्रीय विपदा है। हमारी कोशिश तो यह जरूर होती है कि हम प्राकृतिक प्रकोप पर काबू पा सकें, लेकिन फिर भी प्राकृतिक प्रकोप से लड़ना ज़रा इतना आसान नहीं है।

हमारे यहां उपग्रह बन रहे हैं। माननीय सदस्य ने इनसैट की चर्चा की है। इस बारे में जो हुआ है, वह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उपग्रह बनाने के काम में दिन-रात लगे हुए हैं। दूसरे देशों के उपग्रहों से भी हम फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि हम बाकायदा उनसे मदद लेते रहें। हमारी कोशिश है कि हम उपग्रह बनाएं।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या अब की बार उससे सूचना मिली थी ?

श्री बालेश्वर राम : मीट्रियालोजिकल डिपार्टमेंट ने खुद ही सूचना ली और वक्त पर सब को सूचना दे दी। वारनिंग रैडार कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम, मद्रास और कारेकाल में है। स्थानीय रेडियो केन्द्र मद्रास, विशाखापत्तनम और विजवाडा में है। उन्होंने आध आध घंटे पर वारनिंग्ज रिले कीं। वहां के चीफ सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट के दूसरे उच्च अधिकारियों को भी यह सारी खबर दी गई कि तूफान आने वाला है।

श्री हरिकेश बहादुर : रेडार की एफिशेंसी को बढ़ाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बालेश्वर राम : आपने जो सजेस्शन दिया है, हमने उसे नोट किया है। हम उसको जरूर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

दूसरी बात आपने रिलीफ पहुंचाने के सम्बन्ध में कही है। 250 रुपये जो मैंने कहे हैं, वह एक्स-ग्रेशिया कहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना रीलिफ का काम तुरन्त शुरू किया है। जब भी कोई विपदा आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ढंग से रिलीफ का काम करती हैं। आपने जो सजेशन्स दिये है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। अभी राज्य सरकारें मार्जिनमनी को खर्च करने के लिये स्वतन्त्र है, जिस तरह से भी हो सके वे राहत पहुंचायें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े, इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें चाहे तो तुरन्त मदद कर सकती हैं और इसके लिये हमने कहा भी है कि रिलीफ-वर्क तुरन्त शुरू होना चाहिये और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। आगे जब उनके बस की बात नहीं होगी तो वे हमसे मांग करेंगे और जैसा कि मैंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी, जो भी इम्दाद दी जाती सकती है वह पहुंचाई जायेगी।

आपने रिलीफ कार्यों में भ्रष्टाचार की भी चर्चा की है। मैंने नहीं कहा कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता है। होता होगा, यह इतना बड़ा देश है, कई कामों में कमजोरी होती होगी लेकिन हम जो सार्वजनिक कार्यकर्ता है उनको भी देखना चाहिये कि ऐसे कामों में भ्रष्टाचार न होने पाये। हमें भी इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि स्थानीय प्रशासन को चुस्त रखा जाये ताकि भ्रष्टाचार न होने पाये।

जो साइक्लोन प्रोन क्षेत्र है वहां पर शेल्टर बनाये गये है। आंध्र में भी बने हैं और तामिलनाडु में तो काफी बने हैं वेस्ट बंगाल में भी बने है और केरल में भी बने है। यह हो सकता है कि जितने शेल्टर्स की आवश्यकता हो उतने न बन सके हो ! आप यह भी जानते है कि जैसा लोगों का स्वभाव होता है, यह मछुआरे जो है वह समुद्र के किनारे रहते है मछली पकडने का काम करते है इसलिये वे जल्दी वहां से हटना नहीं चाहते है। यह कठिनाई भी सामने आती है लेकिन कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर्स बनाये जायें (व्यवधान)

अगर वहां टीम भेजने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी भेजी जाएगी। अभी तो जो रिपोर्ट आई है वह मैंने सदन के सामने रख दी है। जो वहां पर नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया जा रहा है। यहां पर हाई पावर कमेटी जिसमें एग्रीकल्चर, फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर रहते हैं, वह बैठती है और समीक्षा करती है।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उन्होंने कौन सा रिलीफ कोड लगाया है ?

श्री बालेश्वर राम : यह तो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है, इसकी उनको छूट है ।

श्री डी० पी० यादव : सारा सिस्टम ही गलत है, कोई कोड नहीं है और न कोई प्रोसीजर है । राज्य सरकार के आफिसर्स जैसा चाहते हैं करते हैं ।

श्री बालेश्वर राम : उनके पास जो मार्जिन मनी और खाद्यान्न है उससे अगर नहीं कर पायेंगे तो हमसे मदद चाहेंगे । यहां पर जो हायस्ट कमेटी है, जिसमें तीनों बड़े इम्पार्टेंट मिनिस्टर्स बैठते हैं, वे समीक्षा करके फैसला लेगें । 75 परसेंट तक गवर्नमेंट आफ इंडिया देने के लिए तैयार रहती है । पहले जायजा लिया जाएगा उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे ।

आपने यह बात भी कही कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बिना सूद के ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री हरिकेश बहादुर: अगर आप बैंक्स को डायरेक्ट कर दें तो वे कर सकती हैं ।

श्री बालेश्वर राम : जैसा कि आप जानते हैं, बैंक्स एक कार्मशियल आर्गेनाईजेशन हैं, यह ठीक है उनको सामाजिक काम भी करने चाहिए लेकिन वे फ्री आफ इन्ट्रेस्ट लोन दे सकेंगी, ऐसा शायद सम्भव नहीं हो पाएगा । स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी रिलीफ देना चाहें वह दे सकती हैं ।

(व्यवधान)

कोटेश्वरन कमेटी में डी०डी० आई० के लोग भी हैं । उसकी सिफारिश के मुताबिक आंध्र की गवर्नमेंट साइक्लोन की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं । दूसरी समिति की जो आपने चर्चा की, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

वहां से जो मांग आती है, उस पर यहां हाएस्ट लेवल पर विचार होता है । जिस अनुदान की आवश्यकता हम समझेंगे, उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तूफान के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, वह, मेरे ख्याल से जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, उससे कुछ अधिक नहीं है । मुझे ऐसा लगा कि मंत्री जी के वक्तव्य को उनके अधिकारियों ने विशेष कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किये बिना तैयार कर दिया है ।

मान्यवर, जहां हम तूफ़ान की बात करते हैं तो दो-तीन प्रश्न उभर कर सामने आते हैं । एक तो यह कि क्या हमने पहले पूर्वानुमान लगाया था या पहले से कोई सूचना प्राप्त की थी ? उन सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद हमने क्या कदम उठाये थे ? पिछली बार इन्सेट एक-ए ने सूचना दी, मौसम केन्द्र ने दी, दिल्ली के केन्द्र ने दी, राडार ने दी और चित्र भी भेजे गये, सचिवों को सूचना भेजी गई । एक जून को और तीन जून को समुद्री तूफान आता है; सैकड़ों लोगों के जीवन और लाखों रुपये की सम्पत्ति को क्षति होती है । उस समय भी सरकार ने कह दिया कि हमने सूचना दे दी थी और आकाशवाणी ने भी कह दिया था । अब यह बात सामने आई है कि 15 अक्तूबर को सूचना प्राप्त हो गई, 16 और 17 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से तूफान गुजरता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 1 अक्तूबर को सूचना प्राप्त होने के बाद जो क्षति हुई, उसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय किये गये थे ? जैसे ही सरकार को सूचना मिली, उसके बाद सरकार ने तुरन्त क्या पग उठाये ? क्या वहां के लोगों को

निकालने का प्रयास किया गया ? अगर किया गया तो क्या ? क्या यह बात भी उस समय तक अंधेरे में रह जाएगी जब तक कि कोई अनुमान लगेगा और सदन के सामने कोई बात आयेगी ? जब तक सदन के सामने कोई बात आयेगी तब तक बात पुरानी हो जाएगी ।

मान्यवर, 1910 से 1980 तक बंगाल की खाड़ी में 500 बार भीषण समुद्री तूफ़ान आ चुके हैं और कई तो बड़े भयानक तूफ़ान आये हैं । पिछली तीन जून को उड़ीसा में तूफ़ान आया था । कहने का मतलब यह है कि इस तरह से तूफ़ान आते रहते हैं और क्षति होती रहती हैं और आप कहते रहते हैं कि हमने यह राहत दे दी, वह राहत दे दी । सब से बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आपने इन्सेट एक ए के बाद से मौसम से सम्बन्धित दुनिया की जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए कोई समझौता किया है ? पता नहीं, आपने किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त की या नहीं । अगर की है तो किस से और क्या ? मेरे विचार में आपको विदेशी एजेंसियों से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, वह बीस टाईम में तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगी लेकिन वार के टाईम में स्थिति खराब हो सकती है । उसके लिए तो आपके प्रयास होने चाहिए । पता नहीं आप कर रहे हैं या नहीं, आप सोच रहे हैं या नहीं । लेकिन यह हो सकता है कि दूसरी एजेंसियों से वार टाईम में सूचनाएं रुक सकती हैं ।

मान लीजिए, आपने दुनिया के सारे मौसम विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर लीं, और इस तरह से इस साल और अगले साल तूफ़ान आते रहे तो ले मेन या साधारण व्यक्ति के दिमाग में तो यह बात रहेगी कि सूखा पड़ेगा, वर्षा होगी क्या आपने इस बारे में कोई कारगर उपाय करने के बारे में सोचा है ?

एक प्रश्न यह है कि जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, उसके लिए आपने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दे रखे हैं ? अगर दे रखे हैं तो सरकारों ने उन पर अमल करने की कोशिश की है या नहीं ? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं ?

मान्यवर, चार सौ झोंपड़ियां और चार सौ लोगों को वहां से हटाना पड़ा । पता नहीं आपने उन चार सौ लोगों को पहले से क्यों नहीं हटाया (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : दश हजार घर गिर गये ।

श्री राजेश कुमार सिंह : दस हजार घर गिर गये, पता नहीं वहां से लोगों को पहले हटाया गया या नहीं ? इसका जवाब मंत्री ने अपने वक्तव्य में नहीं दिया, जो कि उन्हें देना चाहिए था । जहां भी इस प्रकार की स्थिति होती है, वहां पर राहत की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए । उड़ीसा में भी जब 113 करोड़ की मांग थी तब 7 करोड़ दे दिया गया और कहा गया कि बाकी के लिए विचार कर रहे हैं । सभी जगह पर यही स्थिति होती है । इसलिए मेरा कहना है कि राहत की सही व्यवस्था होनी चाहिए ।

जहां तक मौसम विज्ञान की बात है, हम काफी अरसे से विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मोनेक्स के सदस्य हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मौसम विज्ञान के बारे में हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं । आज आप कहते हैं कि मछुए वहां से जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, लेकिन यह बात नहीं है । असली बात यह है कि लोगों को शिक्षित नहीं किया गया है ।

[श्री राजेश कुमार सिंह]

जब लोकदल के लोग एशियाड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये खेल विरोधी हैं। लेकिन करोड़ों रुपया एशियाड पर खर्च करने वाली सरकार सिर्फ 25 करोड़ रुपया मौसम अनुसंधान पर व्यय करती है। जब कि एक दिन के आयोजन में सैकड़ों करोड़ रुपया बरबाद हो जाएगा। हम खेल विरोधी नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यह पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। करोड़ों का नुकसान होता रहेगा, लाखों की जानें जाती रहेंगी।

मेरी मांग है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से मानसून के बारे में एक महीना पहले भविष्यवाणी होनी चाहिए। मानसून को संभावित तिथियों का संकेत पहले ही मिल जाना चाहिए। जून से सितम्बर के मध्य तक 100 दिनों में कुल कितनी वर्षा होगी, इसकी भी भविष्यवाणी होनी चाहिए। उससे काफी फायदा होगा। चक्रवात की जानकारी भी मिलनी चाहिए। इससे ड्राउट और फ्लड दोनों समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ये सारे बुनियादी मुद्दे हैं। अगर जानकारी पहले से प्राप्त हो जाएगी तो इन समस्याओं से निपटने में काफी आसानी होगी।

मदद के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो ढाई सौ रुपया और 20 किलो अनाज प्रति परिवार को दिया गया है, यह बहुत ही अपर्याप्त है। संयुक्त परिवार हैं, 20 किलो अनाज कितने दिन तक चल सकेगा। इसके लिए और कोई आप सहायता देने जा रहे हैं या नहीं ? मेरा निवेदन है कि ढाई सौ रुपये को बढ़ा कर इस समय कम से कम 5000 रुपये तो आप कर दीजिए और एक क्विंटल अनाज भी दीजिए, क्योंकि अनाज के अलावा और कोई चीज उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती। अनाज खा कर ही जीवित रहते हैं। फल नहीं खाते हैं। फूड फार वर्क प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं।

मौसम विज्ञान के सम्बन्ध में जो उपलब्धियां हैं, उनका सही उपयोग हो और पूर्वानुमान मिलने पर कारगर कदम उठाए जाएं। हमने देखा है कि शेल्टर वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं। उनका सही रूप होना चाहिए।

13.00 hrs.

केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें है केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इस समस्या के साथ जुड़े हुए हैं।

श्री बालेश्वर राम : माननीय उपाध्यक्ष जी, (व्यवधान) . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply only to the points raised. He need not take so much time as the hon. Member took.

श्री राजेश कुमार सिंह : आज मैंने दक्षिण भारत के अखबारों में देखा है, तूफान की 6 जिलों में अब भी संभावना बनी हुई है। उसके लिए भी कोई कदम उठाया गया है या नहीं और क्या वहां के लोगों के लिए चेतावनी के साथ-साथ व्यवस्था भी की जा रही है क्योंकि फिर 6 जिले चले गये तो आप कहेंगे कि हमने आकाशवाणी से कह दिया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has come out in the press also.

श्री बालेश्वर राम : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे अखबार की कोई जानकारी इस वक्त नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं और मैं सूचना ले रहा हूं। स्टेट गवर्नमेण्ट के डक्कन हेरल्ड में निकला है, वह आन्ध्र प्रदेश से निकलता ही है, उनको

पता होगा और तैयारियां उन्होंने कर रखी है ।

जो प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, आमतौर से सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे ही दिया है और जो हरिकेश बहादुर जी ने प्रश्न उठाये थे मिलते-जुलते सारे प्रश्न इनके वही हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास जो रडार्स हैं, 15 तारीख को सूचना मिलते ही यहां से सारी खबर पहुंच गई और जो डिफरेन्ट रेडियो स्टेशन हैं, वार्निंग देते रहते हैं, वहां से, राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि कुछ लोगों को हटाया जाए जो एकदम तटवर्ती इलाके में पड़ते थे ।

श्री राजेश कुमार सिंह : जब आपको सूचना प्राप्त हुई तो क्या लोगों को हटाने का प्रयास किया गया ?

श्री बालेश्वर राम : प्रयास किया गया कि वहां से लोगों को हटाया जाए । कुछ लोग हटे भी और कुछ सुरक्षित स्थानों पर भी गए । नेल्लोर, प्रकासम, गुण्टर डिस्ट्रीक्ट वगैरह में काफी लोगों को हटाया गया । मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक इन जिलों के लोगों को वहां से हटाया गया । लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गये, यह तो बहुत बड़ी घटना हुई । थोड़ासा हम लोगों को राहत इस बात से है कि सरकार को भी जितना अधिक नुकसान होने की संभावना पहले व्यक्त की गई थी उसमें जो तूफान की गति थी उसमें कमी रही । इस वजह से कुछ कम नुकसान हुआ, नहीं तो कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचता और उसका कुछ फायदा भी हुआ है । जैसे—तमिलनाडु के कुछ जिले हैं वहां वर्षा भी हुई, जहां काफी सूखे की स्थिति थी वहां वारिश हुई, उससे फायदे भी हुए हैं और भारत सरकार हमेशा सतर्क रहती है ।

पिछले साल जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था, 56 करोड़ रुपये की मदद यहां से भारत सरकार ने पहुंचाई । जैसा मैंने कहा, एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट भी किया गया । सरकार यह जरूर कहती है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। 20 कि० ग्रा० अनाज भी दिया है । अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, साल भर के लिए तो देते नहीं हैं, लेकिन जब तक रिलीफ का पीरियड रखतें हैं और मापदण्ड राज्य सरकार निर्धारित करती है कि हमको रिलिफ ऑपरेशन अभी चलाना है । उसने खुद रिलिफ का काम तेजी से शुरू भी किया है । जैसा मैंने कहा है, भारत सरकार उन्हें और भी मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी । कुछ और सुझाव आपने और हरिकेश जी ने दिए हैं, हमने उनको नोट कर लिया है ।

श्री मनी राम बागडी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह रस्म पूरी करनी है इसलिए यह रस्म पूरी कर रहा हूं । गांधी का देश है । नाम गांधी का जो राष्ट्रीय पिता थे, लंगोटी बांधते थे और उस राष्ट्रपिता को मानने वाले कमलापति जी जैसे महान पुरुष यहां बैठे हैं । जिस देश में एक प्राणी के जीवन के वास्ते 2 करोड़ रुपया, गुल्ली-डंडे के खेल-कूद के लिए 25 करोड़ रुपया और तूफान के अन्दर मरने वाले, उजड़ने वाले लोगों के लिए 2 करोड़ रुपया, बीस सेर चावल मदद के लिए बोला था और जब यहां पर तूफान, बाढ़ और भूख का सवाल आता है तो ऐसे बोलते हैं जैसे गांधी बोलते हैं । गांधी की सन्तान वैसे ही बोलती है जैसे बड़े आदमी चर्चिल और लार्ड बेवल की बोलती थी, ऐसा मालूम देता है । प्राणी प्राणी में कितना अन्तर किया जाता है इसको आप देखें । एक प्राणी के लिए तो दो करोड़ रुपया और दूसरी तरफ करोड़ों

[श्री मनी राम बागड़ी]

प्राणियों के लिए दो करोड़ रुपया। ठीक है डा० लोहिया आज देश में नहीं हैं और यह लोक सभा पंद्रह आने के विचार से वंचित हो गई है। अब तो करोड़ों की बात चलेगी। राव साहब क्या कर सकते हैं? कोई भी मंत्री पूर्ण तो है ही नहीं। किसी मंत्री के पास कान हैं तो जीभ नहीं है और उसकी आंख कटी हुई। किसी का हाथ कटा हुआ है। किसी का दिमाग फटा हुआ है। टूटे फूटे शरीर के अंगों वाली यह सरकार है। कहीं कान पूरा है, कहीं आंख लेकिन शरीर पूरा नहीं है। कितने मरे हैं इसका भी पता नहीं है। इसका भी पता चलेगा जब विदेश से पता लगेगा। विदेश का कोई संगठन है, वह अगर इनको बताएगा तब इनको पता चलेगा कि इतने आदमी मरे हैं। अगर वह सो जाए तो इनको पता ही नहीं चल सकेगा। राव साहब को ज्यादा दोष मैं नहीं देता हूं। उनके बस की यह बात नहीं है। राव साहब को जब तूफान आता है तो जो सरकारी महकमे हैं उन से इत्तिला भी नहीं मिलती है। वह कृषि मंत्री हैं। उन में इतनी शक्ति होनी चाहिए थी कि वह इत्तिला ले सकते। हाथ भी चलें, पांव भी चले, कान भी चलें और आंख भी चले तब काम बनता है। इनको साधन मिलें तभी तो यह बता सकते हैं। आज तो आकाशवाणी से पीपा बजा दिया जाता है। लेकिन जो साधन चाहियें वे उपलब्ध नहीं है। इनमें इतनी शक्ति नहीं है, इसको मैं मानता हूं, ताकत नहीं है इसको मैं मानता हूं। एशियाड में लठ चल रहे हैं। बालिन्दर सिंह को भी पता चल गया है। राव साहब भी जाते तो ये भी न बचते। अच्छा हुआ नहीं गए। भीष्म जी बैठे हैं। ये कर्म के भीष्म नहीं हैं, नाम के ही हैं। ये भी बच नहीं पाते। आगे जो होने वाला है उसका यह द्योतक है।

राव साहब से मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ लम्बा वह सोचें। उनको चाहिए कि वह कलम लगाएं और कुछ करें। प्रदर्शनवाजी से काम चलने वाला नहीं है। शोषित वर्ग का वह सोचें, शोषण करने वालों के बारे में नहीं। करोड़ों लोगों का खून चूस कर एक ताज बना दिया गया जो अपने आप में एक अजूबा है। इस तरह का अजूबा वह भी कोई कर दिखायें, ऐसा अजूबा बना सकते हैं, तो बनाएं। ऐसा वह नहीं कर सकते हैं तो करोड़ों लोगों की जिन्दगियों को वह बचा नहीं सकेंगे। उनकी जिन्दगियों को बचाने के लिए यह जरूरी था कि कलम लगाई जाती। अकाल पर यहां बहस होती, उस पर चर्चा चलती तो सारे तथ्य आपके सामने आते। यह जो ब्यान उन्होंने दिया है इससे साफ मालूम पड़ता है कि दिमाग उनका नहीं है, खोपड़ी उनकी नहीं है। इस में हैदराबाद का दिमाग लगा हुआ है। वह सड़ी हुई खोपड़ी है। आपस में वहां जूते चल रहे हैं। राज दरवार में रोना मचा हुआ है, तूफान में मरने वालों की कौन चिन्ता करेगा? सरकार वहां चल नहीं पा रही है। जनता को बचाने वाला कोई है, कहा नहीं जा सकता है। जब यह पूछा गया कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं तो किसी को याद आ गया और उसने कह दिया कि चार सौ। नहीं तो छः सौ भी लिखे जा सकते थे। लेकिन चार के साथ दो विन्दयां लगा दो हैं। 401 नहीं, 399 नहीं बल्कि पूरे चार सौ। कैसे चार सौ हो गए, पता नहीं --

श्री रत्नसिंह राजदा : (बम्बई दक्षिण) : चार चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : बदले ही तो हैं, मरे तो नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप अपनी बात कहिए ।

श्री मनीराम बागडी : आप जरा रोशनी में आ जाओ, आपका चेहरा देख लूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं, गांव का आदमी किसान के दर्द को जानता है, राष्ट्रपिता ने गलत बात नहीं कही थी कि आजादी के बाद सबसे पहला अगर मेरा काम हो तो राष्ट्रपति या वाइसराय लाज को अगर मिटाऊं नहीं तो कम से कम अस्पताल जरूर बनाऊंगा । झोंपड़ी वालों को आप 250 रु० देते हैं जिसको बीमारी में ढाई आने की गोली नहीं मिलती है, ऐसे देश के अन्दर एक व्यक्ति 350 कमरों के मकान में रहेगा और बीमारी होगी तो करोड़ों रु० लगेगा । अगर यह बात चलेगी तो चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सूखा हो, उस देश के अन्दर करोड़ों इन्सान भूख से मरेंगे । राव साहब, आप जरा गांवों में कदम टेक दो । आप खुद मौके पर जाओ । यह ठीक है कि भगवान तो नहीं हो कि जाने से मोक्ष हो जायगा, लेकिन आपके जाने से जगह पकड़ी जायगी । आप एशियाड प्रदर्शनी में सुन्दर-सुन्दर लड़कियों के फोटो को दिखा रहे हो, अच्छा नक्सा देश का दिखा रहे हो जिससे बाहर के लोगों को मालुम हो कि सारा देश ऐसा ही है । लेकिन जिस देश के अन्दर 10 करोड़ लोग भूखे सोते हों उससे आंख नहीं मोड़ी जा सकती । माननीय कमलापति जी जानते हैं, बने बैठे हैं बेचारे भीष्म पितामह, द्रौपदी का चीर लुट रहा है और चुप बैठे हैं । आप मंत्री जी खुद मौके पर जाइये । यह जो लघु बयान है इसको बन्द कीजिए । लोगों का 20 सेर अनाज और 250 रु० दे कर बेइज्जत न कीजिए । बल्कि जरूरत के मुताबिक उनके मकान बनाइये । आपको तो पहले समाचार मिलता है । राव साहब, आपके तो पुरखे ऐसे होते थे कि एक महीना पहले अपनी मौत बता देते थे कि बेटे इकट्ठे हो जाओ एक महीना बाद मरेंगे । तो क्या सरकार को तूफ़ान का भी पता नहीं लग रहा है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have forgotten that cyclones in coastal regions of Orissa, Andhra Pradesh and Tamil Nadu is the subject of today's Calling Attention. I am just reminding you.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Cyclones in the entire country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister will reply only to the points which concern the subject of this Calling Attention. Please conclude. How is all this relevant?

श्री मनो राम बागडो : साइक्लोन पर ही बोल रहा हूं । मैं तीन बातों का जवाब चाहता हूं ।

(1) जब भी साइक्लोन आये, तूफ़ान आये तो केन्द्र का मंत्री फौरन मौके पर पहुंचे । चाहे कितना ही जरूरी काम हो उसको छोड़ कर वह मौके पर जाये ।

(2) यह नहीं कि जितना मांगे दे दो । कोई तुम हातिम ताई के खजाने पर नहीं बैठे हो । जानते नहीं तुम्हारा कान पकड़ कर झटका देगी रानी कि तुम क्यों गलत बोल गए । केन्द्रीय सरकार जितना उचित समझे उतना जरूर दे । यह जवाब भी वेग है कि जितना

मांगे उतना देंगे । जितना कायदे से बनता है उतना दो । इसका कायदा बनाइये । आपके पास कायदा नहीं है कि किस तरह से पैसा बांटा जाए ।

(3) मरने वालों को मुआवजा, और जिनकी क्षति हुई है उनको मुआवजा दिया जायगा । इन तीन चीजों का आप यहां पर ऐलान कीजिए ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) उपाध्यक्ष जी, हमारे बागड़ी जी तो गांधी जी की भाषा बोलते हैं, इन्होंने हमें बहुत उपदेश भी दिए और जो कुछ इन्होंने कहा हमने उसे नोट किया है । हमारे लिए तो वह उपदेश ही होता है । यहां पर उन्होंने तीन प्रश्न पूछे । लेकिन मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि यह तूफ़ान वहां 18 तारीख यानी परसों रात को ही आया था । सिर्फ कल का ही एक दिन हमें मिला और इस दौरान जितनी सूचना हम एकत्र कर सकते थे, उतनी सूचना एकत्र करने की हमने पूरी कोशिश की । जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी माननीय सदस्य से उसे छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है, हमें उसे छिपा नहीं सकते । यदि कोई यहां से तूफ़ान के दिन भी चला जाता तो उस को राहत मिल सकती थी । लेकिन आपको सही जानकारी देने के लिए सही सूचना एकत्र कर आप तक पहुंचाने के लिए हमारा यहां रहना जरूरी था ।

आन्ध्र प्रदेश की 30–35 टीमें वहां पर रिलीफ के काम कर रही हैं और वह स्थिति का पूरा जायजा ले रही हैं कि वहां पर तूफ़ान के कारण कितना नुकसान हुआ है । जैसा मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, जिस तेजी से उस समय उड़ीसा में तूफ़ान आया था, उसमें भारत सरकार ने 56 करोड़ रुपये की स्टेट को मदद दी थी । इस बार का तूफ़ान वैसा नहीं निकला, जैसी हमें अपेक्षा थी जिसका हमें डर था । वह तूफ़ान उस गति से नहीं आया । लेकिन हवा काफी तेज चली और 70 किलोमीटर प्रति घण्टा उसकी रफ्तार थी । वह तूफ़ानी हवा ही चली....

श्री मनीराम बागडी : मेरे प्रश्न तीन थे, आप नोट कर लीजिए —(1) क्या मंत्री जी मौके पर वहां जाएंगे (2) क्या लोगों को मुआवजा मिलेगा और (3) इस तूफ़ान से प्रभावित लोगों को सहायता देने का क्या कायदा है ?

श्री बालेश्वर राम : मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि सहायता देने का क्या कायदा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want the Minister to go when the cyclone is on, or when it is over?

श्री मनीराम बागडी : जिस जगह यह घटना घटी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां कोई मंत्री जाएंगे । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन लोगों का वहां नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं और तीसरा प्रश्न है कि तूफ़ान पीड़ितों के लिए क्या आपके पास कोई कोड है, जैसा कि फैमीन कोड आपने बनाया हुआ है । यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई संहिता बनाने का आपका विचार है या नहीं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He does not want you to go when the cyclone is on, but after the cyclone is over.

श्री बालेश्वर राम : मैंने कहा कि जहां जिस तरह का नुक्सान होता है, जैसा पिछले साल उड़ीसा में हमने 56 करोड़ रुपये की सहायता दी, क्योंकि वहां का तूफ़ान ज्यादा बड़ा था । इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंटस भी अपने यहां कुछ मापदंड स्थापित करती है कि हमने इतनी मदद

करनी है । फिर जितना यहां से सम्भव हो सकेगा, हम वह कर ही रहे हैं और यहां से मदद देते हैं । इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई मापदण्ड ही नहीं है । जरूरत के अनुसार सहायता हमने पहुंचाई है । लेकिन यह सब क्षति पर निभर करता है कि वहां किस तरह की क्षति होती है । यदि ज्यादा क्षति होती है तो हम ज्यादा सहायता देंगे , यदि कम होती है तो कम मदद करेंगे । लेकिन इसके लिए कोई स्टैण्डर्ड मापदण्ड बनाना बड़ा मुश्किल है । हमने राज्य सरकार को यह भी कह रखा है कि वह वहां यह निश्चित करे कि उसे कितनी इमदाद की और आवश्यकता है और जितना हमसे सम्भव होगा, हम देते हैं ।

दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या वहां पर कोई मंत्री जाएंगे । मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारे लोग समय पर वहां जाते रहते हैं । जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहां जाएंगे, वैसे आन्ध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं । फिर यह साइक्लोन 70 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आया । जब पहले ही वहां पर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मौजूद हैं तो फिर हमारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं है । तामिलनाडु से भी वहां पर चीफ मिनिस्टर ने आना था, लेकिन उनका जाना साइक्लोन की वजह से रूक गया । जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां एक क्षेत्र रायलसीमा का है, जहां काफ़ी समय से सूखा पड़ा आ रहा था, वह सूखा प्रभावित क्षेत्र था, इसी प्रकार तंजाबूर हमारे तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी इस तूफ़ान आने के कारण बारिश हुई और सूखे से राहत मिली है । वहां पर भी एक इंच बारिश रिकार्ड हुई है । इसलिए जहां एक ओर इस तूफ़ान से नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ फायदा भी हुआ है । फिर, जैसा हमने कहा, और इन्फार्मेशन भी हम एकत्र कर रहे

हैं, हमारी 34–35 टीमें वहां पहले से सर्वे का काम कर रही हैं । यदि किसी और इमदाद की जरूरत होगी, तो वह प्रबन्ध भी हम करेंगे ।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Deputy-Speaker, Sir...

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your name is not there; please sit down.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I am told that Shri Salve will make a statement in Rajya Sabha at 2.00 P.M.

13.18 hrs.

STATEMENT *RE.* PRODUCTIVITY LINKED BONUS FOR EMPLOYEES OF GOVERNMENT OF INDIA PRESSES

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Mr. Speaker, Sir, I wish to make a brief statement regarding the decision taken by Government about grant of productivity linked bonus to the employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing under the Ministry of Works and Housing.

The scheme of productivity linked bonus, presently applicable to the Railways and Posts & Telegraph employees, has been extended to about 15000 employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing under the Ministry of works and Housing. These employees have also been allowed 15 days salary/wages as productivity linked bonus on an *ad hoc* basis for the year 1980-81.

The eligibility criteria for bonus will cover all employees of the Government of India Presses and branches of the Directorate of Printing, borne on regular establishment and drawing upto Rs. 1600 per month as basic pay and dearness allowance. In case of officials, drawing more than Rs. 750 but less than Rs. 1600 per month *ad hoc* bonus will be calculated only on the basis of Rs. 750 per month.